[Shrimati Sarla Maheshwari]

मांग को लागू नहीं किया जा रहा है । 5 फरवरी, 1990 को गजट नोटिफिकेशन किया गया और नोटिफिकेशन के पहले ही केन्द्रीय मंत्रिमण्डल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डिपार्टमेंट आफ पर्सनल तथा वित्त मंत्रालय से अनुमोदन भी हासिल कर लिया गया । लेकिन इसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ । सरकार से इस बात को मनवाने के लिए पिछले वर्ष ही इन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, आमरण अनशन भी किया था । मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इस बार भी सरकार उसी समय चेतेगी जब हमारे ये प्रोग्राम स्टाफ के कर्मचारी आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार कर लेंगे और आमरण अनशन के चलते हमारे रेडियो और दूरदर्शन के एकाध कर्मचारी असामयिक मौत के शिकार बन जाएंगे । क्या तभी सरकार की आंख खुलेगी । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं कि सरकार हमारे इन प्रोग्राम स्टाफ के कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दे क्योंकि आज तक उनका प्रोमोशन नहीं हो रहा है । उनका प्रोमोशन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि उनके डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही है । सिर्फ बैठक नहीं हो पाने के कारण उनका प्रोमोशन नहीं हो पा रहा है । यहां तक कि ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव्स का 100 प्रतिशत का कोटा निर्धारित होने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है... (समय की घंटी) उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी जल्दी घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार इन प्रोग्राम स्टाफ के कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दे ताकि उन्हें आमरण अनशन का रास्ता न अख्तियार करना पड़े और जो नेपथ्य में रहकर देश की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति सरकार अपने कर्तव्य का इजहार करे तथा उनकी मांगों को पूरा करे ।

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): The Minister should intervene and call the officers concerned... (*Interruptions*)...

THE VICE- CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shri Pramod Mahajan. Each speaker will get three minutes' time.

Theft of Petrol from Igatpuri Railway Yard

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, रेल यार्ड से छोटी बड़ी चोरी होना अपने आप में कोई समाचार या खबर नहीं है । लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान रेल यार्ड से पैट्रोल की लगभग 60 करोड़ रुपये की चोरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य रेलवे में दिल्ली से मुम्बई जाते समय इगतपुरी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहां सभी गाड़ियां रुकती हैं । यहां इंडियन आयल कम्पनी का बहुत बड़ा डिपो है जहां से आने वाली, जाने वाली सारी गाड़ियों को पैट्रोल दिया जाता है । गत चार महीनों से धीरे धीरे यह पता चला कि इस पैट्रोल में कमी आ रही है तब इस कमी की जांच करने का प्रयास हुआ । मिलना मुश्किल था । लेकिन एक दिन जब सुबह चार बजे एक पैट्रोल का भरा हुआ टैंकर इगतपुरी के गांव के पास कीचड़ में फंस गया, उसे निकालना मुश्किल था, तो साढ़े पांच बजे उस टैंकर में से पूरा पैट्रोल खाली करके वे खाली टैंकर लेकर चले गये । स्वाभाविक रूप से लगभग 20 लाख रुपये का पैट्रोल जब नाली में बहने लगा तो पुलिस को संदेह हुआ । यह कौन टैंकर का मालिक था जो बिना क्रेन लगाये हुए इसको उठाने के लिए पूरे 20 लाख का पैट्रोल खाली कर सकता है । उससे धीरे धीरे यहां तक पहुंचे कि केवल एक टैंकर नहीं था, गत चार महीनों में ऐसे सैकड़ों टैंकरों में भरकर सुबह दो से पांच बजे के बीच में इंडियन आयल कम्पनी का तेल वहां से चोरी किया जाता था । आज यह माना जाता है कि लगभग चोरी हुए तेल की मात्रा 60 करोड़ रुपये के आसपास है । इंडियन आयल कम्पनी की ओर से मध्य रेलवे पर मुकदमा चलाने का भी विचार हो रहा है कि उन्होंने हमारे तेल को संभाल कर नहीं रखा । जैसे कि

बोफोर्स में सबने चर्चा की। कहते हैं कि वह 55 करोड़ रुपये का मामला था। लेकिन एक इगतपुरी रेलवे यार्ड में अगर 60 करोड़ का तेल चोरी हो सकता है तो ऐसे अनगिनत रेलवे यार्ड हिंदुस्तान में जगह जगह है, तो मैं समझता हूं कि इसका हिसाब लगाना लगभग मुश्किल है कि कितने करोड़ का तेल चोरी होता होगा। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि इस सारी बात की वे जांच करें और पैट्रोल जो बहुत ही मूल्यवान है उसको चोरी होने से बचायें, इंडियन आयल कम्पनी को बचायें, रेल को ठीक ढंग से चल यें। इतनी ही प्रार्थना है।

श्री नरेश पुगलिया (महाराष्ट्र): मैं एसोसियेट करता हूं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। रेलवे से काफी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और खासकर रेलवे मिनिस्ट्री सीबीआई से जांच करवाये और मुझे उम्मीद है कि करोड़ों रुपये का पैट्रोल जब इस ढंग से रेलवे स्टेशन से चोरी होता है तो उसमें चाहे रेलवे रहे या पैट्रोल मिनिस्ट्री रहे... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): That's all. You have associated.

Non-payment of salary to employees of Bisra stone lime company of S.A.I.L.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY (Orissa): Sir, this is regarding one serious matter which I raised in this august House last year on the 23rd August, 1990 regarding non-payment to 5500 employees working under Bisra Stone Lime Company Ltd. at Biramitrapur, Orissa. At the intervention of the then Minister of Steel and Mines, the payment was made.

Sir, this is the biggest dolomite and limestone mine in the whole of Asia. After the take-over of this company by the Government of India, its headquarters is located at Calcutta. The Executive Director has not visited this place since long. 5500 workers, out of which 80 per cent are tribal people, are not getting their wages since June, 1991. Sir, to my Special Mention last year the Minister of Steel and Mines assured me that "the default in the payment of wages to employees is a symptom of the sickness of this unit. Therefore, all possible assistance is being rendered to the company to improve its health. The company needs to reduce its cost of production and increase its sales turnover to be able to meet the liabilities. The reduction in the cost of production can be achieved through retrenchment of surplus manpower and mechanisation of mining operations. However, this option is not preferred in view of its implication to the large number of local Adivasi employees." The production cost is not recovered because the steel plant has not reached its target production of one lakh tonne which is less by 30,000 tonnes from the target of one lakh tonnes per month. Now after Vizag Steel Plant linked for purchasing lime stone from this mine. The production has reached target minimum of one lakh tonne per month this year. I don't understand after this assurance by the Government why these employees are not being paid since June. I would like to request, through you, the hon. Minister to intervene again and see that these 5500 poor adivasi workers get their salaries like the headquarters employees at Calcutta are getting their salaries regularly. It is alleged that the Executive Director is also not visiting this site.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, I associate myself. I urge upon the Government to make payment to the poor Adivasi workers who are suffering.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): I associate myself.

Likely closure of Cycle Corporation of India Ltd.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, I want to make this Special Mention about the apprehen-